



अध्याय -द्वितीय  
संबंधित साहित्य का अध्ययन

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 संबंधित साहित्य का अध्ययन

## अध्याय - द्वितीय

### संबंधित साहित्य का अध्ययन

#### 2.1 प्रस्तावना :

विभिन्न समस्याओं से संबंधित शोध साहित्य विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में बहुधा मिल जाता है। परन्तु अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्या से संबंधित शोधकार्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं ?

वर्तमान में देश की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा है। क्योंकि बिना शिक्षा के सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में प्रायः शैक्षिक समस्याएँ पर्याप्त है। अतः इन शोध समस्याओं ने शोधार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया एवं शोध समस्या संबंधी विभिन्न लेख प्रकाशित हुये इसलिए शासन ने उन्हें विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराना आवश्यक समझा इसके अंतर्गत कुमार कृष्ण (1998), दुबे श्यामचरण (2000), चौरसिया विजयकुमार (2004), आधुनिक भारतीय शिक्षा (2006), कुरुक्षेत्र (2006), जनसत्ता (2008), कुरुक्षेत्र (2008), शोधार्थी वर्मा सूर्या (2009), ऑल इंडिया स्कूल एज्युकेशन सर्वे (एन. सी.ई.आर.टी.) आदि को सम्मिलित किया गया है। जिसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है :-

#### 2.1 संबंधित साहित्य का अध्ययन :-

- कुमार, कृष्ण (1998).

“जिस शैक्षिक-अनुभव से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के जीवन में सुधार लायेगा, वही अनुभव इन समूहों के युवाओं के लिए इस प्रशिक्षण का माध्यम बन जाता है कि वह समाज में अपनी अधिनस्थता को आत्मसात कर ले यह बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा की पाठ्य-सामग्री चाहे जो भी हो वह अनुसूचित-जाति और जनजाति के लोगों को

मदद देती है कि वे नौकरियों के लिए योग्यता हासिल करें. जो इनकी पहुँच से पारंपरिक रूप से परे रही हैं।

“यह भी सत्य है कि इस तरह के लोगों की सफलता इन समूहों के अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है फिर भी अनुसूचित-जातियों और जनजातियों के अधिकांश बच्चों के लिए आज की शिक्षा हतोत्साहित करने और नीचा दिखाने वाला अनुभव है ये अधिकांश बच्चे शिक्षा के ऐसे स्तर तक नहीं पहुँच पाते कि वे अपने लिए आरक्षित ऊँचे पदों को ग्रहण करने की योग्यता हासिल कर सकें।”

- **कुमार, कृष्ण (1998).**

“अभी तक भारत में कितने अनपढ़ होंगे एवं दुनियाँ के अंत में अनपढ़ों का प्रतिशत शताब्दी के अंत में कितना होगा? इन्हीं सवालों के जबाब ज्यादातर अधिवेशनों के भाषणों में आंकड़ों के साथ दिये जाते हैं। स्पष्ट रूप से सामूहिक साक्षरता को हासिल करने की कोशिश में हमारी उपलब्धि हमारी निराशाजनक शिक्षा-प्रणाली का केन्द्रीय विषय है। शिक्षा-प्रणाली के प्रसार का साक्षरता पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं हुआ। प्राथमिक-शिक्षा तो उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार आजादी के बाद के 40 वर्षों में केवल 33 गुना बढ़ी हैं। लेकिन कुल आबादी के साक्षरों का प्रतिशत केवल दुगुना ही हुआ है। एक हद तक इस सच्चाई की व्यवस्था आबादी में वृद्धि की बात कहकर की जा सकती हैं। किन्तु इस व्याख्या से देश में फैली हुई निरक्षरता को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता।

प्राथमिक-शिक्षा की स्थिति इतनी खराब क्यों हो रही हैं? इस सवाल का जबाब प्रायः भारत के देहातों में पायी जाने वाली आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में दिया जाता है। प्रायः स्कूल बच्चों को इतने लंबे समय तक क्यों नहीं रख पाते कि वे हमेशा के लिए साक्षर हो जाये? इस सवाल का जबाब प्रायः देहाती (आदिवासी) अभिभावकों की गरीबी का हवाला देकर दे दिया जाता है।

“गरीबी और संस्कृति” की धारणा पर केन्द्रित अध्ययनों का आज भी बोलबाला है और वे हमें यही बताते हैं कि “उनकी हैसियत आर्थिक रूप से अच्छी नहीं होती कि वे अपने बच्चों को काम पर न भेजकर स्कूल भेज दे।”

- दुबे, श्यामचरण (2000).

जनजातियों की पहचान के लिए जिन तत्वों का सहारा लिया गया है वे निम्नलिखित हैं-

1. जनजातियों की जड़े इस देश में बहुत पुरानी है। वे इस भू-भाग के सर्वप्रथम निवासी भले ही न हो पर निश्चित रूप से यहाँ के पुरातन निवासियों में से एक हैं।
2. वे वनों जंगलों एवं पर्वतों में एकांत रहते हैं। उनका परिवेश अगम्य भले ही रहा हो, किन्तु उनकी दूरी ने सांस्कृतिक प्रभावों पर स्वाभाविक नियंत्रण रखा है।
3. जनजातियों का इतिहास बोध सीमित और उथला है उनका स्मरण किया हुआ इतिहास पाँच-छः पीढ़ियों से अधिक का नहीं होता इसके बाद वह जातीय मिथकों से जुड़ जाता है।
4. उनके आर्थिक एवं प्रविधिक विकास का स्तर ऊँचा नहीं होता।
5. अपनी संस्कृति, समग्रता, भाषाओं, संस्थाओं, विश्वासों एवं प्रयासों के आधार पर समाज के शेष भागों से वे अलग दिखायी पड़ते हैं।
6. जनजातीय समतावादी भले न हो कि उनका आंतरिक स्मरण और विशेषीकरण बहुत कम होता है।

- चौरसिया, विजयकुमार (2004).

इन्होंने अपनी पुस्तक “प्रकृति पुत्र बैगा” में लिखा है कि “बैगा-जनजाति की शिक्षा का स्तर क्षेत्रीय-संस्थाओं व विकास आधारित न होने के कारण यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होना चाहते हैं। बैगाओं को शिक्षित करने के लिए नाम पर अब तक पचासों लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। चूँकि बैगाओं

का प्रमुख व्यवसाय खेती हैं इसलिए वे मवेशी पालने एवं चराने के लिए संतानों पर निर्भर होते हैं उन्हें यह भय हमेशा बना रहता है कि यदि उनका कोई लड़का पढ़-लिख गया तो शहर चला जायेगा ऐसी स्थिति में अनेक मवेशियों को कौन चरायेगा? अतः यदि कृषि-शिक्षा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाये तो शायद यहाँ कुछ शैक्षणिक विकास संभव है।

- **आधुनिक भारतीय शिक्षा, (एन.सी.ई.आर.टी.)2006.**

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 में स्पष्ट ज्वलंत रूप से वर्तमान प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं को रेखांकित किया गया है। 'सबके लिए शिक्षा' भारत के भौतिक और अध्यात्मिक-विकास की बुनियादी आवश्यकता बताया है जिसकी सहायता से संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्म, निरपेक्षता और लोकतंत्र की प्राप्ति हो सकती है।

प्रमुख शैक्षणिक समस्याओं की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई है:-

1. महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा।
2. अनुसूचित जातियाँ/जनजातियों की शिक्षा।
3. शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों का शैक्षिक विकास।
4. अल्पसंख्यक, विकलांगों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा।
5. शिक्षा का पुर्न: गठन।
6. शिक्षा का व्यवसायीकरण।
7. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की समस्या।
8. शिक्षा व्यवसाय में सुधार।
9. शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना।

- **कुरुक्षेत्र, (2006).**

बजरंग भूषण और बैजनाथ पाण्डेय ने अपने लेख "ग्रामीण भारत की एक जटिल समस्या: निरक्षरता" में लिखा है कि "ज्ञानम् तृतीयम् मनुजस्य नेत्रम्" अर्थात् ज्ञान मनुष्य का तृतीय क्षेत्र है किन्तु वर्तमान में यह वाक्य

फिसलता प्रतीत हो रहा है इसका प्रमुख कारण निरक्षरता हैं। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार “राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है।” वही दूसरी और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1940 में एक शिक्षक सम्मेलन में कहाथा कि “बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर वह जिम्मेदारियाँ वखूबी नहीं निभा सकता।” किन्तु निरक्षरता के रहते शिक्षा प्रसार कैसे संभव है ?

निरक्षरता का अर्थ ‘अक्षर विहीनता’ है। भारत में जनगणना आयोग 1991 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति जो किसी भारतीय भाषा को समझ के साथ लिख एवं पढ़ सकता हो “साक्षर” कहलाते हैं। यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं जिनमें दो तिहाई लड़कियाँ है इसका प्रमुख कारण लिंगभेद हैं। प्राथमिक शिक्षा में केवल 43.3 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। प्राथमिक स्कूलों की दूरी एवं महिला शिक्षकों का आभाव बालिका-शिक्षा के संदर्भ में मंदक का कार्य करते हैं। भारत में अभी भी प्राथमिक-शिक्षा में केवल 36 प्रतिशत महिलाएं प्राथमिक-शिक्षिका है। वर्तमान में भारत की साक्षरता लगभग 65.38 प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता सिर्फ 54.16 प्रतिशत हैं अर्थात् यदि बच्चा स्कूल में दाखिला ले भी लेता है तो बीच में ही स्कूल छोड़ देता है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे 5वीं तक की एवं 55 प्रतिशत बच्चे 8वीं तक की शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाते है। इसका सर्व प्रमुख कारण प्राथमिक शालाओं में शौचालयों की अनुपयुक्ता, अधिक शिक्षा अधिक दहेज की मान्यता, छोटे बच्चों की देखरेख, बालिका शिक्षा को व्यर्थ समझना, पाठ्य सामग्री का आभाव अध्यापकों की कमी, सुदूर बस्तियों में सरकारी-नीतियों का आभाव, 30 प्रतिशत प्राथमिक-स्कूलों में ब्लेक बोर्ड का आभाव, 80 प्रतिशत प्राथमिक-विद्यालयों में पर्याप्त कमरे नहीं है, 45 प्रतिशत प्राथमिक-विद्यालयों में टाट-पट्टी नहीं हैं, 1/3 विद्यालय मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, सरकारी विद्यालयों के मूल्यांकन का आभाव और

शिक्षकों के समय-समय पर अतिरिक्त कार्य लेना भी राजनीतिका शिकार है। फलतः भारत के पिछड़े-जिलों में 97 प्रतिशत निरक्षरता (महिला हेतु) व्याप्त है।

- जनसत्ता, (2008).

जनसत्ता 10 फरवरी 2009 के लेख 'बेहाल है बैगा' में लेखक प्रसून लतांत ने लिखा है कि "महाभारत में मेकल पर्वत-श्रृंखला के पहाड़ों पर सदियों से निवास कर रहे बैगा-जाति के लोग अब बेहाल हैं। परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि आज वे विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी हैं। इस जनजाति को भारत-सरकार ने 'अत्यंत पिछड़ी जनजाति' की श्रेणी में रखा है। बैगा आज भी बदहाल है न उन्हें ठीक से खाना जुटता है और न उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। वे कुपोषण एवं अन्य तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं इनमें शिक्षा एवं जागरूकता का बेहद आभाव है।

- कुरुक्षेत्र, (2008).

कुरुक्षेत्र के लेख 'अनुसूचित जाति के एवं जनजाति की शिक्षा का प्रयास व परिणाम' बेजनाथ पंडित ने लिखा है कि "शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा द्वारा है ज्ञान कौशल व कला को निखारा जाता है, उसके व्यवहार को परिमर्जित किया जाता है। शिक्षा के आभाव में मानव-जीवन पशुवत प्रतीत होता है।

स्वतंत्रता पश्चात् से ही शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य रखा गया। संसद में 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1992 के दस्तावेजों का संकल्प दोहराया गया। लेकिन आज भी, देश में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया गया देश के 6-14 आयु समूह के 19.4 करोड़ बच्चों में से 6.64 प्रतिशत बच्चे स्कूल से दूर 31.7 प्रतिशत बच्चे स्कूल में बने न रह सकें।

- शोधार्थी वर्मा, सूर्या (2009).

इन्होंने अपने लघुशोध प्रबंध “बैगा-जनजाति की भौगोलिक स्थिति एवं वन संसाधन उपयोगिता का अध्ययन” (डिण्डौरी जिले के विशेष संदर्भ में) लिखा है कि ‘दि शैड्यूल ऐरियाज एण्ड ट्राइबल कमीशन’ ने जनजातियों को चार वर्गों में रखा है इनमें से सबसे अविकसित जनजातियों के क्षेत्रों को “शैड्यूल ऐरिया” या “अनुसूचित क्षेत्र” कहते हैं।

मध्यप्रदेश में सात विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं जिनमें बैगा\*, भारिया, कोरवा, कमार, आबूझमारिया, सहारिया, बिरहोर हैं। इनका रहन-सहन, खानपान, संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, परंपराये, चिकित्सा-पद्धति अन्य जनजातियों से भिन्न हैं इनी आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का प्रतिशत जनजातियों के प्रादेशिक औसत से कम हैं इस कारण इन्हें भारत-सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के उपवर्ग में रखा गया है।

- ऑल इंडिया स्कूल ऐज्युकेशन सर्वे, (एन.सी.ई.आर.टी.) -

“अनुसूचित-जनजाति की जनसंख्या वाली 69.84 प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक-विद्यालय हैं तथा आधे किलोमीटर की दूरी पर 07.01 प्रतिशत एवं एक किलोमीटर की दूरी पर 8.01 बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय हैं।”

प्रयासों पर नजर डाली जाये तो अभी तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित नहीं हो पाया। कभी प्रयासों में नहीं बल्कि क्रियान्वयन में हैं या उनके प्रति वांछित वर्गों की निष्क्रियता से हैं।